कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

जनवरी-फरवरी 2023 अंक-09, वर्ष-03

निबंधक की कलम से

सहकारी समितियों को नई पहचान देते कॉमन सर्विस सेंटर (C.S.C)

राज्य के लैम्पस एवं पैक्स कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों के लिए जाने जाते रहे हैं तथा कृषकों को समय पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने के अलावा उन्हें उर्वरक, बीज कीटनाशक दवाएं एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराना उनके प्रमुख कार्य रहे हैं।

विभाग ने राज्य के लैम्पस पैक्सों को समय के साथ बदलने की दिशा में कदम उठाते हुए सर्वप्रथम राज्य के अच्छे लैम्पस पैक्सों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करवाते हुए उनका कंम्पयुटरीकरण कराना प्रारंभ किया। पूर्व से जिन लैम्पस/पैक्स में कंम्प्यूटर उपलब्ध थे उनके अलावा वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के में कुल 829 लैम्पस/पैक्स को कंम्प्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष भारत सरकार की सहकारी समितियों के कंम्प्यूटरीकरण योजना के तहत राज्य के लैम्पस/पैक्स को कंम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

लैम्पस/पैक्स के कंम्प्यूटरीकरण के साथ ही उनको कॉमन सर्विस सेंटर (C.S.C) (प्रज्ञा केन्द्र) के रुप में विकसित करने का कार्य अभियान चलाकर प्रारंभ किया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारियों एवं सी0एस0सी के जिला कार्यक्रम प्रबंधकों एवं उसके राज्य स्तरीय नोडल ऑफिसर के साथ लगातार कई दौर की बैठकों एवं कार्यों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया गया कि लैम्पस/पैक्स में यह कार्य सुचारु रुप से प्रारंभ होकर सफलतापूर्वक चले।

राज्य के 591 लैम्पस एवं पैक्सों ने C.S.C के रुप में कार्य करने हेतु आई0डी प्राप्त किया जिसमें से वर्तमान में 524 समितियां C.S.C के रुप में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए न सिर्फ अपने सदस्यों को वरण अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को प्रज्ञा केन्द्र की तरह राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की ई0सेवाएं एवं उसके लाभ उपलब्ध करा रही हैं।

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ई–श्रम कार्ड योजना के तहत राज्य के सभी असंगठित गरीब मजदूरों/कामगारों का एक केन्द्रीकृत डाटाबेस तैयार करने हेतु उनका पोर्टल पर निबंधन किया जाना था। राज्य के लैम्पस/पैक्सों ने C.S.C के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य करते हुए लगभग 52000 श्रमिकों/कामगारों का पंजीकरण ई–श्रम पोर्टल पर कराया।
- लैम्पस एवं पैक्स द्वारा ग्रामीण ई–स्टोर के रुप में कार्य करते हुए सोलह लाख रुपये से अधिक कीमत की विभिन्न वस्तुओं के 447 क्रय ऑर्डरों को पूरा करने का कार्य किया।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जरुरतमंद गरीब कृषक, मजदूर एवं अन्य कमजोर तबके के वैसे लोग जो A.T.M अथवा बैंक में जाकर अपने खाते से रुपये निकालने में कठिनाई महसूस कर रहे थे वैसे 66207 ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल दस करोड़ 20 लाख 58 हजार 261 रुपये डिजी पे के माध्यम से निकासी कर उन्हे उपलब्ध कराये गये।
- डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम कुल 55 हजार पांच सौ चौवालीस व्यक्तियों को 400 प्रकार विभिन्न प्रकार की ई0सेवाएं उपलब्ध कराई गयी जिससे समितियों को 14565270.91 (एक करोड़ पैंतालिस लाख पैंसठ हजार दो सौ सत्तर रुपये इक्यानवे पैसे मात्र) रुपयों की आय हुई।
- इस अवधि में सिर्फ C.S.C के कार्य एवं लाभ हेतु एक लाख पचास हजार व्यक्तियों का आगमन लैम्पस एवं पैक्स में हुआ।
- सभी प्रकार की योजनाओं के तहत अभी तक कुल 11 करोड़ 72 लाख रुपयों से अधिक का कारोबार C.S.C के तहत सहकारी समितियों के द्वारा किया गया है।

कॉमन सर्विस सेंटर (C.S.C) राज्य के लैम्पस एवं पैक्सों को ना सिर्फ नई पहचान दे रहे हैं, बल्कि उनमें नवीन तकनिकी का समावेशन करते हुए उद्यमी (Entrepreneur) की भावना एवं गुणों को भी विकसित करते हुए देश दुनिया से सीधे जोड़ रहे हैं।

हमारा लक्ष्य है राज्य के प्रत्येक लैम्पस/पैक्स अपने अन्य कार्यों के अलावा कॉमन सर्विस सेंटर के रुप में भी कार्य करें।

शुभ कामनाओं सहित।

मृत्युंजय कुमार बरणवाल
निबंधक

पशुपालन एवं सहकारिता भवन रांची, में मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह

पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हेसाग, रांची में 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह में सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी0, मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। इस शुभअवसर पर मुख्य अतिथि के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तथा ध्वज को सलामी दी गयी।

ध्वजारोहन के उपरांत भवन के सभागार में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दो घंटे से अधिक समय तक चले कार्यक्रम में बाहर से आये कलाकारों के द्वारा राष्ट्रभक्ति गीतों सहित, गजल, सूफी गीतों आदि की खूबसूरत प्रस्तुति से पूरा सभागार संगीतमय हो गया। उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारीगणों ने पूरे कार्यक्रम को खूब सराहा तथा उसका आनन्द उठाया।

समारोह में विभागीय सचिव के साथ–साथ निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची एवं पशुपालन निदेशक सपरिवार कार्यक्रम की समाप्ति तक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विभागीय सचिव के द्वारा काफी सराहना की गयी एवं भविष्य में भी गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने हेतु प्रोत्साहन दिया गया।

सहकार से समृद्धि

- विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत भण्डारण क्षमता स्थापित करने की योजना इससे सहकारी समितियों से जुड़े किसान अपनी उपज समय पर बेचकर उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
- अगले पाँच साल में हर पंचायत में नई बहुउद्देशीय सहकारी समिति, प्राथमिक मत्स्यजीवी समिति और डेयरी सहकारी समिति स्थापित की जाएगी।
- 31 मार्च 2024 तक गठित विनिर्माण क्षेत्र की सहकारी समितियों को 15% कर दायरे में ही रखने का निर्णय लिया गया।
- प्राथमिक कृषि साख समिति (PACS) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) के लिए नकद जमा और ऋण के लिए नकद निकासी कर TDS को 3 करोड़ रू0 तक सीमित करने और प्रति सदस्य 02 लाख रू0 तक की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- चीनी सहकारी समितियों के किसानों को वर्ष 2016–17 से पहले किए गए भुगतान को उनके व्यय में दिखाने की सुविधा दी गयी है।
- सहकारी चीनी मिलों को 10 हजार करोड़ रू0 की राहत मिलेगी।
- किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और अन्य हाशिए के वर्गों के लिए, सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा देगी।

₹ केन्द्रीय बजट एक दृष्टि में

- विनिर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने वाली नई सोसायटी पर 15% की रियायती दर से कर लगाने तथा नकद निकासी पर TDS के लिए 03 करोड़ रू0 की उपरी सीमा तय करना शामिल है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,150.38 करोड़ रू0 का कुल बजट परिव्यय निर्धारित किया गया है।
- हलांकि यह राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 के संशोधित अनुमान 1,624.74 करोड़ रू0 से 474.36 करोड़ कम है।
- सहकारिता के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था।
- "सहकार से समृद्धि" इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही 2,516 करोड़ के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया है।
- सभी हितधारकों और राज्यों के परमर्श से पैक्स के लिए मॉडल उप नियम तैयार किए गए, जिससे वे बहुउद्देशीय पैक्स बन सकें।
- सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है।

सफलता की कहानी

ज्योति देवी, प्रगतिशील महिला किसान

माया एंजेलो का यह उदाहरण झारखण्ड की राजधानी राँची के नगड़ी ब्लॉक के हरही गाँव की ज्योति देवी (30) के जीवन को परिभाषित करता है ।

ज्योति देवी एक संयुक्त परिवार में रहती है। वह अपने परिवार की बड़ी बहू है और अपने पति, दो बेटे, देवर, देवरानी, दो भतीजे और अपने सास ससुर के साथ रहती है। उनके परिवार की जीविका डेरी और कृषि पर निर्भर है। 2012 में ज्योति देवी का विवाह जीतेश शाही से होने के पश्चात वे अपने नए परिवार के साथ डेरी एवं कृषि में सहयोग करने लगी।

2017 से ज्योति देवी अपने गाँव में झारखंड दुग्ध महासंघ; जिसका प्रबंधन वर्तमान में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा किया जा रहा है, के सहयोग से बनी दुग्ध संग्रहण केंद्र से जुड़ी है और 2021 में बनी हरही दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड की शेयरहोल्डर है। वर्तमान में उनके पास 22 गाय 15 बाछी है। 22 गायों में से 13 गायों से अभी कुल 170 लीटर दूध उत्पादन हो रहा है जिसमे से 10 लीटर दूध घर के खपत के बाद नियमित रूप से 160 लीटर दूध प्रतिदिन ज्योति देवी समिति में दे रही है जहाँ से दूध आगे झारखंड दुग्ध महासंघ द्वारा संचालित मेधा डेयरी को भेजा जा रहा है। झारखंड दुग्ध महासंघ से ज्योति देवी को उनके द्वारा दिये गए दूध का भुगतान उनके निजी बैंक खाते में हर 10 दिन के चक्र में होता है। 10 दिन के चक्र का मिल्क बिल भुगतान लगभग 56,560 रूपए के करीब होता है। इस तरह दूध से उनकी मासिक आमदनी लगभग 1,69,680 रूपए के करीब होती है। मासिक आमदनी में से हर माह 2 चक्र का भुगतान 1,13,120 रूपए के करीब दूध उत्पादन का लागत है जिसमे पशुओं के खान पान, रख रखाव और 2 मजदूरों का खर्च निकल जाता है और एक चक्र का भुगतान उनके घर के खर्च के लिए उपयोग होता है।

> *"जीवित रहना महत्वपूर्ण है, संपन्नता सुरुचिपूर्ण है !"*

पशुपालन के साथ साथ ज्योति देवी के परिवार के अन्य सदस्य अपने 3 एकड़ जमीन में खेती करते है स्वीट कॉर्न, मक्का, धान, गेहुं इत्यादि। अपने निजी जमीन एवं लीज में जमीन लेकर भी यह हरे चारे जैसे बरसीम, जई, नैपियर भी लगाते है । हरे चारे की पूर्ति के लिए यह अजोला की खेती करते है और साइलेज भी बनाते है ताकि इनका प्रयोग हरे चारे कि कमी के दौरान दुधारू पशुओं में पशु आहार के रूप में किया जा सके।

दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए ज्योति देवी एवं उनके परिवार ने पशु पोषण के साथ पशुओं कि संख्या बढ़ाने और पशुओं कि नस्ल सुधार पर भी ध्यान दिया है। इनकी 15 बाछी कृत्रिम गर्भाधान से हुई है। 15 बाछी में से 2 बाछी साहीवाल नस्ल की और 5 बाछी गिर नस्ल की है। प्राकृतिक गर्भाधान के लिए एक गिर नस्ल का सांड भी इनके पास है। वर्तमान में 13 गाय दूध में है जिनमे से 2 गाय डेन्मार्क से मँगवाए गए semen के द्वारा पैदा हुई है। इन 2 गायों में से 1 गाय 15 लीटर दूध देती है और दूसरी गाय दूसरी ब्यात में 22 लीटर दूध दे रही है। झारखंड दुग्ध महासंघ के सहयोग से, NDDB द्वारा स्वीकृत वैज्ञानिक पशु प्रजनन की प्रक्रिया – Accelerated Breed Improvement Programme के माध्यम से 2 HF गायों में साहीवाल नस्ल का भ्रूण स्थानांतरण (embryo transfer) किया गया है ताकि पैदा होने वाली बाछी अधिक मात्रा में दूध दे सके।

जैविक खेती के लिए ज्योति देवी एवं उनका परिवार वर्मिकम्पोस्ट तैयार करते है। उपजाए हुए स्वीट कॉर्न को मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजेटेबल्स के स्थानीय इकाई को भी बिक्री करते है जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। अपनी पूंजी लगाकर चार क्युबिक मीटर में यह बायोगैस यूनिट भी लगाए हैं जो खाना बनाने के लिए ईंधन का काम दे रहा है और साथ साथ LPG गैस में होने वाले खर्च को कम कर रहा है।

ज्योति देवी को अच्छी दुग्ध उत्पादिका होने के लिए दो बार झारखंड दुग्ध महासंघ द्वारा मेधा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसी वर्ष में उन्हें प्रगतिशील किसान होने के लिए झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है।

इस तरह ज्योति देवी न केवल अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं बल्कि उनका पूरा परिवार कड़ी मेहनत, लगन और अभिनव तरीकों से पशुपालन और खेती करने के लिए झारखण्ड के अन्य दुग्ध उत्पादकों के लिए मिसाल हैं।

किसान पोर्टल

"कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।" – छह दशक पहले महात्मा गांधी ने कहा था। आज भी स्थिति वही है, लगभग पूरी अर्थव्यवस्था कृषि द्वारा संचालित है, जो गांवों का मुख्य आधार है। इसका देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 16% योगदान है तथा भारतीय आबादी के लगभग 52% लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। कृषि में तेजी से विकास न केवल आत्मनिर्भरता के लिए बल्कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी आवश्यक है।

लाखों सीमांत और छोटे किसान होने के बावजूद भारतीय किसान उत्पादन और उत्पादकता में किसी से पीछे नहीं हैं। वे विकसित देशों में किसानों के रूप में उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को कुशलता से अपनाते हैं। उर्वरक, बीज, कीटनाशक जैसे समय पर और पर्याप्त इनपुट के प्रावधान और सस्ती कृषि ऋण/फसल बीमा उपलब्ध कराकर, भारतीय किसान राष्ट्र को खाद्य और पोषण के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

यह महसूस किया गया कि मौजूदा तकनीकी के दौर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से कृषक समुदाय और निजी क्षेत्र को प्रासंगिक जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है। किसान पोर्टल इस दिशा में एक प्रयास है कि एक आम भारतीय किसान के लिए कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के उत्पादन, बिक्री/भंडारण से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं और उनके लिए आवश्यक सभी सूचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप बनाया जाए। इससे भारतीय किसान को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई गई वेबसाइटों के चक्रव्यूह के माध्यम से छानबीन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

किसान पोर्टल में एक बार किसान अपने गांव/ब्लॉक/जिला या राज्य के आसपास विशिष्ट विषयों पर सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यह जानकारी टेक्स्ट, एसएमएस, ईमेल और ऑडियो/वीडियो के रूप में उसी भाषा में दी जाएगी जिसे वह समझता/समझती है। होम पेज पर दिए गए भारत के मानचित्र के माध्यम से इन स्तरों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से विकसित फीडबैक मॉड्यूल के माध्यम से किसान विशिष्ट प्रश्न पूछने के साथ. साथ मूल्यवान प्रतिक्रिया देने में भी सक्षम होंगे।

हमीन कर बजट (झारखण्ड का अपना बजट)

- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) के द्वारा राज्य अन्तर्गत लैम्पस/पैक्स के सुदृढ़ीकरण की महत्वपूर्ण योजना को प्राथमिकता दी गई है।
- सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु 100 MT क्षमता के कुल 566 एवं 50 MT क्षमता के कुल 146 गोदामों के निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- कृषि ऋण माफी योजना तथा सुखाड़ राहत योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
- कृषि ऋण माफी योजना के तहत 45 लाख किसानों के बीच 1727 करोड़ रू0 के ऋण की माफी की गई है।
- सुखाड़ राहत योजना के तहत किसान परिवारों को 3500 रू0 की दर से उनके संबंधित खातों में 411 करोड रू0 हस्तांतरित की गई है।
- पाँच एकड से कम क्षेत्रफल वाले तालाबों की मशीन से गाद हटाने एवं डीप बोरिंग के लिए योजना बनाई गई है। इन तालाबों के लिए 500 करोड रू0 के बजट का प्रावधान किया गया है।
- सौर उर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने हेतु कृषि समृद्धि योजना लागू की गई है।
- फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक नई योजना के अंतर्गत कीटनाशक एवं उर्वरक का उपयोग कम करने तथा जैविक खेती की ओर अग्रसर होने के लिए एक योजना प्रस्तावित किया गया है।
- इस योजना के तहत राज्य में जैविक खेती को बढावा दिया जायेगा और युवा किसानों को खेती से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- फार्मर प्रोडयूसर ऑर्गेनाईजेशन के सशक्तीकरण को लेकर अनुदान मद में 50 करोड रू0 का प्रावधान किया गया है।

वनोत्पाद से किसानों के स्वावलंबन को सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ते कदम

वन उत्पाद के मामले में झारखण्ड पर प्रकृति की विशेष मेहरबानी है। लाह, तसर, शहद, ईमली, चिरौंजी, साल बीज, महुआ आदि झारखण्ड के वनों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। राज्य गठन के बाद से राज्य के किसानों को वन उत्पाद का सही मूल्य दिलवा पाना चुनौती का विषय बना हुआ था। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा अमर शहीद सिद्धो –कान्हो के नाम से ''सिद्धो –कान्हो कृषि एवं वनोत्पाद राज्य सहकारी संघ'' का निर्माण किया, जिसके तहत राज्य के सभी किसानों एवं वन उत्पाद संग्राहकों को संगठित करते हुए उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना तैयार की गयी है। ताकि वनोत्पाद के माध्यम से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती हेतु नव ऊर्जा का संचार किया जा सके।

सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोत्पाद राज्य सहकारी संघ के तहत त्रिस्तरीय संरचना का गठन किया गया है। पंचायत स्तर पर लैम्प्स –पैक्स, जिला स्तर पर सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोत्पाद जिला सहकारी संघ एवं राज्य स्तर पर महासंघ ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि0 कृषि एवं वन उत्पाद के क्षेत्र में मजबूत ब्रांड बनाने की ओर अग्रसर

पैक्स लैंपस को किया जा रहा सशक्त, कार्यशाला का हो रहा आयोजन

किसानों के वनोपज को उचित मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने के उदेश्य से सभी लैम्पस एवं पैक्स को आधुनिक स्वरूप देने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री के दिशा–निर्देश के तहत धरातल पर अब सकारात्मक प्रयास प्रारम्भ हुए हैं। इस कड़ी में सहकारिता के माध्यम से कृषि और वन उपज में आजीविका संवर्धन पर सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में पहली कार्यशाला पशुपालन एवं सहकारिता भवन हेसाग, हटिया रांची के सभागार में 17 फरवरी 2023 को की गयी। कार्यशाला मे सिद्धो –कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची सहित सहकारिता विभाग के पदाधिकारी एवं रांची जिले के 200 से अधिक लैम्पस/सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला मे मुख्य रूप से सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ एवं जिला संघों के गठन के उद्देश्यों, कृषि एवं वनोपज मे राज्य की स्थिति, उसमे व्याप्त संभावनाओं और उसमे लैम्पस/पैक्स की

भागीदारी एवं भूमिका के बारे मे जानकारी दी गई। प्रत्येक जिले में कार्यशाला के आयोजन के बाद जल्द ही सभी लैम्पस/पैक्सों को जोड़ते हुए सदस्यता वृद्धि का अभियान प्रारंभ किया जाएगा । सदस्यों को उनकी कृषि और उपज के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने की योजना भी सरकार की है।

लैम्पस/पैक्स के माध्यम से एक मजबूत ब्रांड को खड़ा करने का प्रयास

मुख्यमंत्री के निर्देश के तहत सिद्धो –कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ के विभिन्न उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी निभाई जाएगी। इसका मूल उद्देश्य जिले के सभी लैम्प्स –पैक्स को उचित बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना, क्षमता निर्माण, प्रसंस्करण और एक मजबूत ब्रांड को खड़ा करना है। । पंचायत स्तरीय समिति उत्पादन एवं संग्रहण का जिम्मा एवं जिला स्तरीय संघ प्रसंस्करण की जिम्मेवारी निभाएगी। विभिन्न सुविधाओं से जोड़ते हुए वनोपज के साथ आगे बढ़ने की जो परिकल्पना की गयी है।

राज्य सरकार द्वारा पहली बार वनोपज को बढ़ावा देने के संगठित प्रयास के परिणाम नजर आने लगे हैं। आगामी तीन वर्षों में सिद्धो –कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ के नेतृत्व में कृषि एवं वन उत्पाद के क्षेत्र झारखंड राज्य को देश में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लक्ष्य के तहत कार्ययोजना बनाकर उसे धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सहकारिता सेवा के परिक्ष्यमान सहायक निबंधकों का अध्ययन भ्रमण

श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान (SKIPA) में 16 सप्ताह से प्रशिक्षणरत झारखण्ड सहकारिता सेवा के पंद्रह परिक्ष्यमान सहायक निबंधकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य के अंदर तीन दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर धनबाद एवं बोकारो जिले में ले जाया गया। अध्ययन भ्रमण में सहायक निबंधकों के सहयोग एवं सहायता के लिए दो प्रशिक्षण समन्वयक भी शामिल थे।

भ्रमण के प्रथम दिन सभी प्रशिक्षार्थी बोकारो जिले के पेटरवार प्रखण्ड स्थित पेटरवार ग्रामीण पॉल्ट्री को–ओपरेटिव सहकारी समिति, चास प्रखण्ड स्थित राधानगर पैक्स तथा बोकारो ईस्पात कर्मचारी क्रेडिट को–ओपरेटिव सहकारी समिति का भ्रमण एवं परिदर्शन कर कुक्कुट पालन की गतिविधियों, पैक्स द्वारा कृषकों एवं अपने अन्य सदस्यों के लिए संचालित विभिन्न प्रकार योनाओं तथा क्रेडिट के क्षेत्र में सहकारिता की भूमिका एवं उपयोगिता को देखा एवं उसकी प्रक्रियाओं को समझा।

भ्रमण के दूसरे दिन बोकारो जिले के चन्द्रपुरा पैक्स द्वारा संचालित आटा मिल एवं बंदियों पैक्स में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण प्लांट तथा कोल्ड रुम को देखा । दोनो समितियों की कार्यकारणी के सदस्यों तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी बोकारो द्वारा विस्तार से सभी प्रशिक्षार्थी सहायक निबंधकों को किये जा रहे कार्यों के बारे में बताया गया तथा उससे क्षेत्र में हो रहे बदलाव एवं लाभ की भी जानकारी दी।

अध्ययन भ्रमण का तीसरे दिन सहायक निबंधकों द्वारा धनबाद जिले के केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, कोयलांचल, अर्बन कोओपरेटिव बैंक लि0, तथा राजगंज पैक्स का परिदर्शन किया गया। दोनो बैंकों के भ्रमण के दौरान सहायक निबंधक सहकारी बैंकों के कार्य के तरीकों तथा इनके विकास में उनकी महत्ती भूमिका से अवगत हुए। राजगंज पैक्स में सहायक निबंधक पैक्स द्वारा संचालित जमावृद्धि योजना एवं कॉमन सर्विस सेंटर की उपयोगिता से अवगत हुए।

अध्ययन सह भ्रमण कार्यक्रम से सभी सहायक निबंधकों ने बहुत कुछ नया सीखा तथा सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली, उनके संचालन के तरीकों एवं उसमें समिति की प्रबंध पर्षद की भूमिका को स्वंय देखा तथा समझा।

सहायक निबंधकों ने कहा कि इस भ्रमण कार्यक्रम से उन्हे काफी लाभ हुआ है जो उनके कार्य करने के दौरान उनके बहुत काम आएगा तथा उन्हे निर्णय लेने में सहयोगी होगा।

सेवा निवृत्ति

झारखण्ड सहकारिता सेवा के वरीय पदाधिकारी, संयुक्त निबधंक, सहयोग समितियां, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र देव रंजन लगभग 34 वर्षों की सेवा के उपरांत दिनांक 28 फरवरी, 2023 को सेवा निवृत्त हो गये।

श्री रंजन ने तत्कालीन संयुक्त बिहार के गया जिले से अपनी सेवा की शुरुआत की थी, उसके बाद उन्होने मुंगेर, सीतामढ़ी, रोहतास भभुआ, चाईबासा, हजारीबाग तथा रांची जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के एम0डी सहित विभाग के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दी।

संयुक्त निबधंक, सहयोग समितियां, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में पदस्थापना के पूर्व श्री चन्द्र देव रंजन संयुक्त निबधंक, सहयोग समितियां, दक्षीणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची के पद पर पदस्थापित थे।

अंतरराष्ट्रीय मिल्लेट (मोटा अनाज) वर्ष

मिलेट जिन्हें हिंदी में मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी, कोदो इत्यादि) कहा जाता है। यह पौष्टिक अनाज होते हैं जो फाइबर, खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। मोटे अनाज अक्सर विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं, और उन्हें दलिया, ब्रेड, और साथ ही भोजन के रूप में भी पकाया जाता है। मोटे अनाजों को दुनिया भर में व्यापक रूप से उगाया एवं भोजन में इस्तेमाल किया जाता है।

भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने 5 मार्च 2021 को वर्ष 2023 को 'इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट' घोषित किया था और भारत की इस मांग को दुनिया के 72 देशों का समर्थन मिला था। 3 मार्च 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए एक संकल्प में 2023 को 'इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट' घोषित करने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने कुछ दिनों पहले ही इटली के रोम में 'इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट–2023 (IYM–2023)' की शुरुआत की है। FAO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि ''IYM2023 हमें जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ–साथ वैश्विक पोषण, खाद्य सुरक्षा, अच्छी नौकरियों और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने की क्षमता वाली फसलों का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा।''

भारत में लगभग 6 से 7 तरीके के मिलेट उगाए जाते हैं, जिसमें पर्ल मिलेट (बाजरा), फिंगर मिलेट (रागी), फॉक्सटेल मिलेट (कंगनी), प्रोसो मिलेट (बारगु), सोरघुम (ज्वार), लिटिल मिलेट (समाई), कोदो मिलेट (अरका) शामिल हैं। FAO का डेटा बताता है कि, भारत में वर्ष 2020–21 में 12 मिलीयन टन मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ और भारत 41% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंकड़े यह भी बताते है कि भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने वर्ष 2021–22 में $64.28 मिलियन मूल्य के मोटे अनाजों का निर्यात किया जो कि वर्ष 2020–21 में $59.75 मिलीयन था। पूरे एशिया में मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का 80% हिस्सा है ।

मिलेट की खपत, बाजार और जागरूकता फैलाने के लिए 66 से ज्यादा स्टार्टअप्स को ₹6.25 करोड़ से ज्यादा की राशि दी गई है, जबकि 25 स्टार्टअप्स को और फंडिंग की मंजूरी दी गई है। भारत में मोटे अनाज की वैल्यू चेन के लिए 500 से भी अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च (IIMR) ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 250 स्टार्टअप को इनक्यूबेट किया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए रेलवे और विमान कंपनियों द्वारा यात्रा के दौरान मिलेट सर्व किए जाएंगे और अलग–अलग देशों के भारतीय दूतावास भी मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन करेंगे। सरकार ने देश के सभी राज्यों को भी मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन करने के लिए पत्र लिखे हैं। ऐसे कई प्रयास हैं जो सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कर रही है।

भारत कई कारणों से मोटे अनाजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि मिलेट सूखा–प्रतिरोधी फसल है जिसे खराब मिट्टी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। जिससे यह भारत के उन हिस्सों में एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत बन जाता है जहाँ अन्य फसलें नहीं पनप सकती हैं। भारत के कुछ हिस्सों में बाजरा एक मुख्य भोजन है, और इसकी खेती और खपत को बढ़ावा देने को स्थानीय समुदायों का समर्थन करने और पारंपरिक खाद्य संस्कृतियों को संरक्षित करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है मिलेट्स में पाए जाने वाले पोषक तत्व जो अनेक रोगों से बचाव करते हैं।

सहकारिता के क्षेत्र में नयी पहल

देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियाँ हैं जिनमें लगभग 29 करोड़ सदस्य हैं, अधिकांश सहकारी समितियां ग्रामीण भारत से हैं। भारत की सहकारी वास्तुकला को मजबूत करने तथा देश की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के साथ समन्वयित स्थापित करने के उद्देश्य से सहकारी प्रक्षेत्र में जुलाई, 2021 के बाद से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेशन किया गया हैं।

- जल वितरण और पेट्रोल/एलपीजी/हरित ऊर्जा वितरण जैसी 25 सेवाओं या गैर–कृषि व्यावसायिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए पीएसीएस के दायरे का विस्तार करना
- एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस स्थापित करना
- एक राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाना
- सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद के लिए GeM पोर्टल पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देना
- नये केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन

खूँटी लैम्पस लिमिटेड, खूँटी

खूँटी लैम्पस लिमिटेड, खूँटी का समस्त क्रियाकलाप चाईबासा रोड पर प्रखण्ड कार्यालय, खूँटी के सामने स्थित भू–खण्ड पर निर्मित कार्यालय भवन –सह–गोदाम से किया जाता है। खूँटी लैम्पस का गठन वर्ष 1976 में किया गया था, जिसका निबंधन संख्या–02/खूँटी दिनांक–10.03.1976 है। लैम्पस का कार्यक्षेत्र समस्त नगर पंचायत, खूँटी तक सीमित है। लैम्पस में कुल 550 सदस्य हैं जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के 102 पुरूष तथा 11 महिला सदस्य, अनुसूचित जाति वर्ग के 21 पुरूष तथा 05 महिला सदस्य एवं सामान्य वर्ग के 389 पुरूष तथा 22 महिला सदस्य हैं।

खूंटी लैम्पस में राज्य योजना के तहत 100 MT के तीन गोदाम निर्मित हैं, जिसके कारण डी0ए0पी0, एन0पी0के0, यूरिया, जैविक खाद एवं सागरिका जैसे उर्वरक एवं गेहूं, चना, मकई आदि बीज का उचित मात्रा में रख–रखाव कर किसानों को ससमय बीज एंव उवर्रक मुहैया कराया जाता है। धान अधिप्राप्ति में भी खूंटी लैम्पस के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है।

प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम में धान अधिप्राप्ति योजना के तहत् वर्ष 2018–19 से किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्य भी वृहद पैमाने पर किया जाता रहा है, जिससे लैम्पस के सदस्य कृषकों सहित आसपास सैकड़ों कृषक लाभान्वित हो रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा लैम्पस में जमा वृद्धि योजना का भी संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत कुल 404 खाते संचालित हैं तथा बचत खाते के 403 खाते संचालित हैं। गृह लक्ष्मी बचत योजना के तहत प्रारंभ में जमाकर्ताओं को एक लॉकरयुक्त लोहे अथवा स्टील का डब्बा दिया जाता था जिसकी चाभी लैम्पस के पास होती थी।

लैम्पस में कॉमन सर्विस सेंटर का भी संचालन किया जा रहा है जिसके माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के ई0 श्रम कार्ड योजना के तहत क्षेत्र के असंगठित मजदूरों एवं कामगारों के निबंधन का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से लगभग 400 प्रकार की विभिन्न ई0 सेवाओं का लाभ भी लोगों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

लैम्पस के अच्छे कार्यों को देखते हुए लैम्पस परिसर में विभाग द्वारा 05 MT का मिनी सोलर कोल्ड रूम का अधिष्ठापन किया गया है कराया गया है, जिसे लैम्पस की कार्यकारिणी निर्णय लेकर अपने कार्यक्षेत्र अन्तर्गत फल एवं सब्जी विक्रेताओं को उचित राशि लेकर किराये पर उपलब्ध करा रही है। इससे ना सिर्फ लैम्पस को आमदनी हो रही है साथ ही फल एवं सब्जी विक्रेताओं को भी अपने सामान को अधिक समय तक सुरक्षित एवं ताजा रखने में सहायता मिल रही है।

लैम्पस की कार्यकारिणी की जागरुकता एवं सभी सदस्यों के सहयोग के कारण लैम्पस लाभ की स्थिति में है तथा अपने सदस्यों की सेवा में तत्पर नजर आता है।

भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया revolution हो रहा है। इस बार के बजट में सहकारिता क्षेत्र को टैक्स संबंधित राहतें दी गई हैं। मैन्यूफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को कम टैक्स रेट का फायदा मिलेगा।

प्रधान सम्पादक : मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक** : जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, कुमोद कुमार, स0 नि0, कालीचरण सिंह, स0 नि0 एवं राजीव कुमार सिंह, व0 अं0 पदा0
निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं अन्नपूर्णा प्रेस एण्ड प्रोसेस, राँची द्वारा मुद्रित।
पता : तृतीय तल, पशुपालन एवं सहकारिता भवन, हटिया - 834004, दूरभाष : 0651-2290444
e-mail : jharkhand.coopregistrar@gmail.com, website : cooperative.jharkhand.gov.in